

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 2008—अगस्त 22, 2008 (श्रावण 25, 1930)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 2008—AUGUST 22, 2008 (RAVANA 25, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवार नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकलनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1013
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	735
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकलनों और असामिकाधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अधीनेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	1171
भाग II—खण्ड-2—विषेषक तथा विषेषकों पर प्रबंध समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित संघों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सामिकाधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपाधिकारियां आदि भी शामिल हैं	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित संघों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामिकाधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित संघों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सामिकाधिक नियमों और सामिकाधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपाधिकारियों भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे संघों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	5961
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामिकाधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालय, निवारक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	469
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंट्स और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	7899
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सामिकाधिक नियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	185
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी नियमों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	*
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*अंग्रेजी प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	than the Administration of Union Territories).....	*
	1013	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PART II—SECTION 3—Sub-Section (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
	755	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
	11	
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government	*
	1171	
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	5961
	*	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	469
	*	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	*
	*	
PART II—SECTION 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	7899
	*	
PART II—SECTION 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	185
	*	

*Folios not received.

बस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
नई दिल्ली-110066, दिनांक 24 जुलाई 2008

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर-360-- अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुर्नगठन किया गया था। भारत सरकार ने श्री सुधीर त्यारी, एच-14, देव विहार, सिविल लाइन्स, मुशदाबाद-244001 (यू०पी०) को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के नए गैर-सरकारी सदस्य तथा उपाध्यक्ष के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। जबकि दिनांक 8 सितम्बर, 2006 (क्रमांक 1, 3,5 एवं 7 को छोड़कर) 23 अक्टूबर, 2006, 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 21 दिसम्बर, 2006, (क्रमांक 2 को छोड़कर) और 22 दिसम्बर, 2006 (क्रमांक 5 को छोड़कर) 5 एवं 10 जनवरी, 2007, 1 फरवरी, 2007 (क्रमांक 1 को छोड़कर) और 14 फरवरी, 2007 (क्रमांक 2,3,4,7,8,9 और 10 को छोड़कर) 2, मार्च, 2007 (क्रमांक 2 को छोड़कर) 7, 9 मार्च, 2007, 8 मई, 2007, (क्रमांक 2 को छोड़कर) 16 मई, 2007, 25 जुलाई, 2007, 3 और 29 अगस्त, 2007, 11 सितम्बर, 2007, 24 सितम्बर, 15 अक्टूबर, 2007, 2 नवम्बर, 2007 और 11 एवं 12 मार्च, 2008, 25 मार्च, 2008 एवं 8 मई, 2008, 17, 23 जून, 2008, 3 जुलाई, 2008 एवं 15 जुलाई, 2008 के संकल्प के द्वारा गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 59 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 84 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ.) संदीप श्रीबास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2008

संकल्प

सं. VI-डी. एण्ड पी./222/07-08/वी.डी.टी. --

समाज के क्रय शक्ति विहीन गरीब वर्गों में व्याप्त क्षय रोग, मलेरिया, काला - अजार, फाइलेरिया आदि जैसी उपेक्षित बीमारियों का सामना करने के लिए औषधि विकास के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इन लोगों को किफायती दाम पर औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण- चरण-I, II और III से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए नई एवं छोटी कम्पनियों सहित भारतीय भेषज उद्योग हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मौजूदा औषधि एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी) के क्षेत्र को और व्यापक करने का निर्णय लिया है। डीपीआरपी के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए फार्मा उद्योग को सहायता हेतु 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 45.0 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के आगे विस्तारित होने पर इस राशि को बढ़ाया जा सकता है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों सभी राज्य सरकारों देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिक संस्थानों को परिचालित की जाए (सीएसआईआर/आईसीएआर/आईसीएमआर/यू.जी.सी./डीआरडीओ आदि) यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजीव नाथ
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2008

सं. एफ. 9-48/2006-यू. 3(ए)---

जबकि केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अधिकार संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि सामान्य भूतीय चेटिल्यार ऐस्ट्रिक्ट एंड एन्युकेशनल ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत चेटिल्यार विश्वविद्यालय, पादुर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु को नए संस्थान के रूप में समविश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 1 जनवरी, 2008 के पत्र सं.एफ. 40-1/2007 (सीपीपी- 1) के द्वाय चेटिल्यार अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी, पादुर, कांचीपुरम जिला एवं पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा करने की शर्त पर, 'भगविश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 22.02.2008 के अपने पत्र संख्या एफ. 40-1/2007 (सीपीपी- 1) के जरिए इस आशय से अपनी सिफारिश में आंशिक रूप से संशोधन किया कि वह दर्जा नई श्रेणी के तहत ही प्रदान किया जाए।

4. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 09.06.2008 के अपने पत्र संख्या एफ. संख्या 40-1/007 (सीपीपी- 1) के जरिए यह रूपान्तर किया है कि अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित सम-विश्वविद्यालयों (i) चेटिल्यार अस्पताल और अनुसंधान संस्थान और (ii) चेटिल्यार कालेज ऑफ नर्सिंग शामिल होंगे।

5. अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ली सलाह पर केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वाय प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वाय घोषणा करती है कि "चेटिल्यार अनुसंधान और शिक्षा अकादमी", पादुर, केलान्डकम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु जिसमें (i) चेटिल्यार अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, पादुर, केलान्डकम और (ii) चेटिल्यार कालेज ऑफ नर्सिंग, पादुर केलान्डकम शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनवार्य 'नए सिरे की' श्रेणी के

तहत समिश्रविद्यालय का दर्जा अस्थायी रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए चेटिनाद अनुसंधान और शिक्षा अकादमी द्वारा नियन्त्रित उल्लिखित शर्तों के अनुपालन और पूरा करने की तारीख से दिया जाएगा :

- (i) चेटिनाद अस्पताल और अनुसंधान संस्थान और चेटिनाद कालेज आफ बर्टिंग की सभी चल और अचल परिस्थितियाँ कालूनी रूप से उनके मूल व्याप अर्थात् यजा युत्तैया चेटिनाद बैरिटेबिल एण्ड एज्युकेशनल द्रुट और चेटिनाद अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी में निहित होगी और छात्रों के भविष्य, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के हित में उच्चतर शिक्षा के मानकों के लिए अनुरक्षण किया गया है; और
 - (ii) उपर्युक्त उल्लिखित दोनों शिक्षण संस्थान उनके सम्बद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् दि तमिलनाडु डा० एम.जी.आर. सेक्विल नूलिनर्सिटी, चेन्नई तमिलनाडु से स्वतं तो अस्पताल करेंगे।
 - (iii) उपर्युक्त उल्लिखित दोनों संस्थानों में राजातकोत्तर पाठ्यक्रम तत्काल आरंभ होने चाहिए।
6. चेटिनाद अनुसंधान और शिक्षा अकादमी को प्रदत्त दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की मदद से प्रत्येक वर्ष के अंत में सभी संबंधित राज्यालयों की समीक्षा की शर्त पर भी होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति और उस पर आयोग की सिफारियों के जरिए प्रति वर्ष आयोजित समीक्षा के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद प्रदत्त दर्जे की पुष्टि की जाएगी।
 7. उपर्युक्त पैरा 5 में की गयी उद्घोषणा उन शर्तों के पूर्ण/अनुपालन के अधीन है जिनका उल्लेख इस अधिकृत्यना के पृष्ठांकन 9 में है।
 8. व तो भारत सरकार और व ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चेटिनाद अनुसंधान और शिक्षा अकादमी अथवा इसकी किसी अंगीभूत शिक्षण इकाईयों को योजनागत और योजनातर के रूप में कोई सहायता अनुदान प्रदान नहीं करेंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2008

संकल्प

विषय:-राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदूर, तमिलनाडु की कार्यकारिणी परिषद् ।

सं. एफ. 15-4/2002 युवा सेवा-2--

इस मंत्रालय के दिनांक 30 दिसंबर, 2004 के समसंब्यक संकल्प के अधिकरण में तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर0जी0एन0आई0याइ0डी) के संगम जापन और नियमों एवं विनियमों के अनुसार में, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की कार्यकारिणी परिषद् का 7 अगस्त, 2007 से पुनर्गठित निम्नलिखित रूप में किया गया है:-

1	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	श्री सी0आर0 केसवन, 53, बजुल्लाह रोड, टी0 नगर, चेन्नै, तमिलनाडु-600017	उपाध्यक्ष
4	संयुक्त सचिव (युवा कार्य), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6	निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	सदस्य
7	कार्यक्रम सलाहकार, राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य

8	डॉ एमोदी० राजीव गौड़ा, सहयोगी प्रोफेसर, आई आई एम, बैंगलूरु, 1361, ९वां क्लास, जेपी नगर १ फेस, बैंगलूरु-५६००७८	सदस्य
9	श्रीमती जयंती मटराजन, अलवरपेट, चेन्नै-६०० ००४	सदस्य
10	श्री सौ० अपोक जामिर, एमएलए एवं पूर्व सांसद (राज्य सभा), यालुजेन, हाल नागर्जन, दीमापुर, नागालैण्ड-७९७११२	सदस्य
11	श्री हर्ष मंडेर, फ्लैट नं० ६२३३, सी-६, वसंतकुञ्ज, नई दिल्ली-११००७०	सदस्य
12	उप कुलपति (पदनाम), गांधीग्राम रुरल इंस्टीट्यूट, समकक्ष विश्विद्यालय, गांधीग्राम-६२४३०२, डिल्लीगुल ज़िला, तमिलनाडु-आइडीएआरए के प्रतिनिधि के रूप में	सदस्य
13	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के चार प्रबंडों के संकाय से एक प्रतिनिधि (बारी-बारी से)	सदस्य
14	श्री दुली चंद जैन, माइसापुर, चेन्नै-६००००४	सदस्य
15	संकाय प्रमुख	सदस्य-सचिव

2 क्र०सं० (1), (2) पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के सिवाय कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य तथा अन्य पदेन सदस्य ७ अगस्त, २००७ से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक उनके उत्तरवर्तियों को निवार्धित/नामित नहीं किया जाता, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे। उपर्युक्त क्र०सं० (३), (४) और (१०) पर सूचीबद्ध सदस्यों का नामांकन क्रमशः १४-१२-२००७, १०-६-२००८ और १०-६-२००८ से प्रभावी होगा।

3 बैठकों में भाग लेने के लिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की कार्यकारिणी परिषद में कार्यरत मंत्री/संसद सदस्य/गैर-सरकारी सदस्य नियमानुसार यात्रा अत्ता/महँगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे।

4 इस विषय पर इससे पहले जारी सभी आदेश/संकल्प तदनुसार संशोधित माने जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है इस संकल्प की प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी जाए।

ए. के. सरण
अबर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2008

संकल्प

विषय: नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय एशमर्शदात्री समिति का गठन।

सं0 7-5/2007-डी.पी.-II भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का खतरा उसकी मौगोलिक स्थिति के कारण बहुत अधिक है। यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मादक पदार्थ एवं शराब का दुरुपयोग करने वाले, विशेषतः सुई छारा नशीली दवा लेने वाले नशा पीड़ितों में, एचआईवी/एड्स के अधिक खतरे ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है।

2. संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार “राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से बिन्न, उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा”।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को अन्य बातों के साथ-साथ मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है।

3. भास्त छारा तीनों संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों अर्थात् (i) स्वापक औषधि संबंधी अभिसमय, 1961, (ii) मनःप्रभावी पदार्थ संबंधी अभिसमय, 1971 और (iii) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार संबंधी अभिसमय, 1988 को हस्ताक्षरित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1998 में अयोजित 20वें विशेष सत्र में मादक पदार्थों की मांग में कमी को मादक पदार्थ नियंत्रण रणनीति के अपरिहार्य स्तम्भ के रूप में स्वीकार किया गया है।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 1985-86 से मादक पदार्थों की मांग में कमी के उद्देश्य से मद्यपान और मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, इस समय देश में मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से 41 परामर्श केन्द्र और 401 नशामुक्ति केन्द्र नशापीडितों का पता लगाने, परामर्श देने, उपचार करने और उनका पुनर्वास करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय ने परामर्श केन्द्र और नशामुक्ति केन्द्र संचालित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण तथा दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समाज स्क्षा संस्थान (एनआईएसडी) में राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण केन्द्र (एनसीडीएपी) स्थापित किया है। मंत्रालय ने स्थानीय सांस्कृतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नशामुक्ति केन्द्रों में कार्य करने वाले सेवा प्रदानकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं मादक पदार्थ दुरुपयोग कार्यक्रमों की विकालत, अनुसंधान और निगरानी के लिए 8 प्रख्यात गैर-सरकारी संगठनों को क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया है। वे मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में कार्यस्त गैर-सरकारी संगठनों को तकनीकी सहयोग भी देते हैं।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के महेनजर, मादक पदार्थों की मांग में कमी विशेषरूप से शिक्षा/जागरूकता सूजन, नशामुक्ति और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शदात्री व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई है। भारत सरकार ने तदनुसार नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो निम्नानुसार है :-

- | | | | |
|------|---|---|-----------|
| I. | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री | - | अध्यक्ष |
| II. | सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री | - | उपाध्यक्ष |
| III. | पदेन-सदस्य | | |

1. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के सचिव :-

- (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- (ii) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
- (iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 - (क) विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग
 - (ख) उच्चतर शिक्षा विभाग
- (iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- (v) युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग
- (vi) महिला और बाल विकास मंत्रालय

2. अन्य पदेन-सदस्य

- (i) सचिव, उत्तर-पूर्वी परिषद, शिलांग
- (ii) महानिदेशक एवं अपर सचिव, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय
- (iii) आयुक्त केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय
- (iv) महानिदेशक एवं अपर सचिव, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
- (v) प्रमुख, राष्ट्रीय व्यसन उपचार केन्द्र - सह-प्रधान, मनोशेग विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स),
- (vi) कार्यकारी निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय।
- (vii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, नई दिल्ली।

IV. राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि :-

पांच राज्य सरकारों के प्रतिनिधि - प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व तथा दो संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एक-एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है।

V. केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के प्रतिनिधि :-

- (i) अध्यक्ष, मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण से संबंधित भारतीय गैर-सरकारी संगठन परिसंघ (फिंगोडैप)।
- (ii) बारी-बारी से नामित किए जाने के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रमुख।
- (iii) शेष क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों को छोड़कर अन्य गैर-सरकारी संगठनों के छः प्रतिनिधि।
- (iv) सामाजिक कार्य/सामाजिक शिक्षा/अन्य संगत क्षेत्रों से जुड़े दो प्रोफेसर।
- (v) मीडिया के दो प्रतिनिधि।
- (vi) उस क्षेत्र से संबंधित चार दिशेषज्ञ/कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता जो नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति से संबंधित हैं।

VI. सदस्य सचिव, पदेन - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव ।

6. नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति का कार्य, केन्द्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में निवारण, नशामुक्ति, पुनर्वास और हानि में कभी से संबंधित मुद्दों के पूर्ण परिपेक्ष्य पर सलाह देना होगा :-

- (i) मद्यपान और मादक पदार्थ दुरुपयोग से प्रभावित और/अथवा ऐसे व्यक्तियों जिनमें नशा पीड़ित होने की प्रबल संभावना है, के लिए नीतियां, कार्यक्रम और विधायी उपाय ।
- (ii) शिक्षा, जागरूकता सृजन और सामुदायिक भागीदारी ।
- (iii) मादक पदार्थ और शराब के दुरुपयोग के पीड़ितों के व्यक्तिगत और सामाजिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के उपाय ।
- (iv) मादक पदार्थ और शराब की मांग में कभी हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन और उसे और प्रभावी बनाने के तरीकों के बारे में लाभार्थियों की राय प्राप्ति ।

7. श्रेणी IV और V के अंतर्गत नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा किन्तु वे अपने स्थान पर नए सदस्यों के नामित होने तक सदस्य बने रह सकते हैं ।

8. नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी ।

9. गैर-सरकारी सदस्यों को भास्त सरकार के संगत नियमों/अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा ।

10. नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों पर होने वाला व्यय मंत्रालय के गैर-योजनागत बजट में से पूरा किया जाएगा ।

**MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)**

New Delhi-110066, the 24th July 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R/360—The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 08th September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct Shri Sudhir Tyagi, H-14, Dev Vihar, Civil Lines, Moradabad -244 001 (U.P.) as new non-official member & Vice-Chairman of All India Handicrafts Board, while retaining all officials and non-official members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08th September, 2006 (except Sl.No.1,3, 5 &7) 23rd October, 2006, 22nd November, 2006 and 27th November, 2006, 5th, 21st December, 2006 (except Sl.No.2) and 22nd December, 2006 (except Sl.5) 5th & 10th January 2007, 1st February, 2007 (except Sl.No.1) and 14th February, 2007 (except Sl.No.2,3,4,7,8,9&10), 2nd March, 2007 (except Sl.No.2), 7th & 9th March 2007, 8th May, 2007 (except Sl.No.2), 16th, May, 2007, 25th July, 2007, 3rd & 29th August, 2007, 11th September, 2007, 24th September, 15th October, 2007, 2nd November 2007, 11th & 12th March 2008, 25th March 2008 and 8th May 2008, 17th June 2008, 23rd June 2008, 3rd July and 15th July 2008.

The present strength of the Board shall be 84 Members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 59 Non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

(Dr.) SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)**

New Delhi, the 23rd July 2008

RESOLUTION

No. VI-D&P/222/07-08/TDT :-

The Government of India recognizing the importance of developing drugs to fight neglected diseases like Tuberculosis, Malaria, Kala-Azar, Filariasis etc. prevalent among poorer sections of society lacking purchasing power have decided to enlarge the scope of the existing Drugs and Pharmaceuticals Research Programme (DPRP) of Department of Science and Technology by way of extending grants-in-aid to Indian pharmaceuticals industry including new and small companies for R&D projects involving clinical trials - Phase-I, II and III to ensure providing medicines to them at an affordable price. An amount of Rs. 45.0 crores has been assigned during the 11th Five Year Plan to help pharma industry for this purpose under DPRP. This amount can be enlarged as the programme develops further.

ORDER : Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments, Government of India all the State Governments, all the Universities and Scientific Institutions in the country (CSIR/ICAR/ICMR/UGC/DRDO, etc.)

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette for India for general information.

SANJIV NAIR
Joint Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 4th August 2008

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a "Deemed-to-be-University".

2. And whereas, applications were received from Rajah Muthiah Chettiar Charitable & Educational Trust, Chennai, Tamil Nadu seeking status of 'deemed-to-be-university' to Chettinad University, Padur, Kancheepuram District, Tamil Nadu, as a 'De Novo' Institution, under Section 3 of the UGC Act, 1956:

3. And whereas, the UGC has examined the said applications and vide its communication bearing F.No.40-1/2007(CPP-I) dated 01.01.2008 has recommended for conferment of status of 'Deemed-to-be-University' to Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Kancheepuram District for a period three years subject to review at the end of each year. Later, the UGC vide its communication F.No.40-1/2007(CPP-I) dated 22.02.2008 has partially modified its recommendations to the effect that the status recommended be awarded under *De Novo* category;

4. And whereas, the UGC vide its letter F.No.40-1/2007(CPP-I) dated 09.06.2008 has *inter alia* clarified that the proposed 'Deemed-to-be-University' Institution will consist of (i) Chettinad Hospital and Research Institute and (ii) Chettinad College of Nursing;

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare that "Chettinad Academy of Research and Education (CARE)", Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil Nadu, comprising (i) Chettinad Hospital and Research Institute, Padur, Kelambakkam and (ii) Chettinad College of Nursing, Padur, Kelambakkam, shall be a "Deemed-to-be-University", under 'De Novo' category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years with effect from the date the CARE Trust complies and fulfils with the below-mentioned conditions:

- (i) All the movable and immovable assets / properties of the Chettinad Hospital and Research Institute and Chettinad College of Nursing shall be legally transferred from their parent Trust, viz., Rajah Muthiah Chettiar Charitable and Educational Trust and vested with the Chettinad Academy of Research and Education (CARE) Trust and registered so in the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education; and
- (ii) Both the aforementioned teaching institutions shall be disaffiliated from their affiliating university, namely, The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai, Tamil Nadu.
- (iii) Postgraduate courses should be commenced at both the aforesaid institutions immediately.

6. The status conferred on Chettinad Academy of Research and Education is also subject to a review of all the institutions concerned at the end of each year by the UGC with the help of an Expert Committee. The status conferred shall be confirmed after a period of five years only on the basis of the reviews to be conducted annually through an Expert Committee of the UGC and recommendations of the Commission thereof;

7. The declaration as made in para 5 above is also subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.9 of the endorsement to this Notification;

8. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Chettinad Academy of Research and Education or any of its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR

Joint Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 1st August 2008

RESOLUTION

No. F. 15-4/2002-YS.II—

Sub: Executive Council of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, Tamil Nadu.

In supersession of this Ministry's Resolution of even number dated 30th December, 2004 and in accordance with the Memorandum of Association and Rules & Regulations of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD), the Executive Council of RGNIYD stands re-constituted with effect from 7th August, 2007 with the following composition:-

i)	Minister of State(Independent Charge), Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi.	President
ii)	Secretary, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi.	Vice-President (Ex-officio)
iii)	Shri C.R.Kesavan, 53, Bazullah Road, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600 017	Vice-President
iv)	Joint Secretary(Youth Affairs), Ministry of Youth affairs & Sports, Government of India, New Delhi.	Member
v)	Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi.	Member
vi)	Director, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development	Member
vii)	Programme Adviser, NSS, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, New Delhi.	Member
viii)	Dr. M.V. Rajeev Gowda, Associate Professor, IIM, Bangalore, 1361, 9 th Cross, JP Nagar I Phase, Bangalore-560078.	Member
ix)	Smt. Jayanti Natarajan, Alwarpet, Chennai-600 004	Member
x)	Shri C. Apok Jamir, MLA & Ex-MP (Rajya Sabha), Walujen, Hall Nagarjan, Dimapur, Nagaland-797112.	Member
xi)	Shri Harsh Mander, Flat No. 6233, C-6, Vasant Kunj, New Delhi-110 070	Member
xii)	Vice Chancellor (by designation), Gandhigram Rural Institute, Deemed University, Gandhigram-624 302, Dindigul District, Tamil Nadu, as representative of IDARA.	Member
xiii)	One representative from the faculty of the four RGNIYD Divisions (by rotation).	Member
xiv)	Shri Duli Chand Jain, Mylapore, Chennai-600 004	Member
xv)	Faculty Head	Member – Secretary

Contd.

2. All members of the Executive Council except the President, Vice President at S.No.(ii) and other Ex-Officio members, shall hold office for a period of three years with effect from 7th August, 2007 or until their successors are elected/nominated whichever is earlier. The nomination of members listed at S.No.(iii), (viii) & (x) above will be effective from 14.12.2007, 10.6.2008 and 10.6.2008 respectively.
3. Ministers/Members of Parliament/non-official members serving on the Executive Council of RGNIYD will be entitled to get TA/DA as per rules, for attending the meetings.
4. All Orders/Resolutions issued earlier on the subject shall stand modified accordingly.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations.

A. K. SARAN
Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 15th July 2008

RESOLUTION

Subject:- Setting up of a National Consultative Committee on De-addiction and Rehabilitation (NCCDR).

No. 7-5/2007-DP-II—

India is situated in a region which is highly vulnerable to the problem of drug abuse, and drug and alcohol abuse is an area of serious concern for the country. The high risk of HIV/AIDS among the drug users, especially, injecting drug users has further aggravated the problem.

2. Article 47 of the Constitution provides that “the State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.”

The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 was enacted to, inter alia, curb substance abuse.

3. India is also a signatory to three United Nations Conventions, namely : (i) Convention on Narcotic Drugs, 1961; (ii) Convention on Psychotropic Substances, 1971; and (iii) Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. The United Nations General Assembly, in its 20th Special Session in 1998, has accepted demand reduction as an indispensable pillar of drug control strategies.

4. For the purpose of drug demand reduction, the Ministry of Social Justice & Empowerment has been implementing the Scheme for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse since 1985-86. Under the Scheme, 41 counseling centres and 401 drug de-addiction centres are functioning in the country with financial assistance of this Ministry for

identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts. The Ministry has set up a National Centre for Drug Abuse Prevention (NCDAP) in the National Institute of Social Defence (NISD) for capacity building and training of Non-Governmental Organisations (NGOs) running Counseling and De-addiction Centres. The Ministry has also nominated eight reputed NGOs working in the field of drug abuse prevention as Regional Resource and Training Centres (RRTCs) for imparting training in local cultural setting to service providers working in various De-addiction Centres and for undertaking advocacy, research and monitoring of drug abuse programmes. They also give technical support to the NGOs working in the field of drug abuse prevention.

5. Against the above background, a need has been felt for a consultative mechanism at the national level to advise Central and State Governments on issues connected with drug demand reduction, especially education/awareness building, de-addiction and rehabilitation. The Government of India has accordingly decided to constitute a **National Consultative Committee on De-addiction and Rehabilitation (NCCDR)** as follows:-

I. Minister for Social Justice & Empowerment - Chairperson

II. Minister of State for Social Justice & Empowerment- Vice-Chairperson

III Ex-officio Members

1. Secretaries in the following Ministries/Departments:

- (i) Ministry of Social Justice & Empowerment
- (ii) Ministry of Finance, Department of Revenue
- (iii) Ministry of Human Resource Development
 - (a) Department of School Education & Literacy
 - (b) Department of Higher Education
- (iv) Ministry of Health and Family Welfare
- (v) Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs
- (vi) Ministry of Women and Child Development

2. Other ex-officio Members

- (i) Secretary, North Eastern Council, Shillong
- (ii) Director General and Additional Secretary, Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs
- (iii) Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance
- (iv) Director General and Additional Secretary, National Aids Control Organisation, Ministry of Health and Family Welfare
- (v) Chief, National Drug Dependence Treatment Centre-cum-Head, Department of Psychiatry, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)
- (vi) Executive Director, Nehru Yuva Kendra Sangathan, Ministry of Youth Affairs and Sports
- (vii) Chief Executive Officer, Prasar Bharati, New Delhi

IV. Representatives of State Governments and Union Territory administrations:

Representatives of five State Governments – one from each region i.e. North, South, East, West and North-East - and of two Union Territories, to be nominated by the Chairperson.

V. Representatives of following categories to be nominated by the Central Government:-

- (i) President, Federation of Indian Non-Governmental Organisations on Drug Abuse Prevention (FINGODAP).
- (ii) Head of four RRTCs to be nominated by rotation
- (iii) Six representatives of other NGOs i.e. other than those remaining RRTCs.
- (iv) Two Professors in the field of Social Work/Social Education/other relevant areas.
- (v) Two representatives of the Media.
- (vi) Four Experts/Activists/Social Workers belonging to the area with which NCCDR is concerned.

VI. Member Secretary, Ex-Officio—Joint Secretary dealing with the subject in the M/o of Social Justice & Empowerment.

6. The functions of NCCDR would be to advise Central and State Governments on the entire gamut of issues related to prevention, de-addiction, rehabilitation and harm reduction, with special reference to the following:-

- (i) Policies, programmes and legislation measures for persons affected by and/or vulnerable to alcoholism and drug abuse.
- (ii) Education, awareness building and community mobilization.
- (iii) Measures to facilitate physical and social rehabilitation of drug and alcohol abuse.
- (iv) Feed back on implementation of the national programme on drug and alcohol demand reduction, and ways to improve their effectiveness.

7. Members nominated under categories IV and V shall have a tenure of three years but will continue till nomination of their successors.

8. The NCCDR will meet at least twice a year.

9. T.A./D.A. etc. to non-official members will be admissible as per relevant rules/instructions of the Government of India.

10. Expenditure on meetings of the NCCDR shall be met from the non-plan budget of the Ministry.

(Dr.) ARBIND PRASAD
Joint Secy.